गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 057
दि. 26.06.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महंगाई की नई मार: मौसम की बेरुखी और वैश्विक संकट ने बिगाड़ा रसोई का बजट

नई दिल्ली। देश में आम आदमी की रसोई पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और देश में मानसून की धीमी रफ्तार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दोहरा असर डाला है। रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल टमाटर, प्याज और आलू के दामों में तेज बढ़ोतरी ने घरेलू बजट को झटका दिया है। इसके साथ ही चावल, गेहूं, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

देश के अधिकांश हिस्सों में जून के दौरान सामान्य से अधिक गर्मी और मानसून के अपेक्षित समय पर पूरी तरह सक्रिय नहीं होने का सीधा असर कृषि गतिविधियों पर दिखाई देने लगा है। किसान खरीफ फसलों की बुआई को लेकर असमंजस में हैं, जबकि मंडियों में ताजा सब्जियों की आवक भी प्रभावित हुई है। उत्पादन और आपूर्ति दोनों पर दबाव बढ़ने से बाजार में कीमतों ने तेजी पकड़ ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून की स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो आने वाले सप्ताहों में खाद्य वस्तुओं के दाम और बढ़ सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा मासिक रिपोर्ट भी महंगाई के बढ़ते दबाव की पुष्टि करती है। रिपोर्ट के अनुसार जून के शुरुआती 18 दिनों में टमाटर की कीमतों में 18.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में प्याज के दाम 6.6 प्रतिशत और आलू की कीमतें 5.6 प्रतिशत तक बढ़ गईं। केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि मौसम संबंधी जोखिम और वैश्विक परिस्थितियों के कारण खाद्य महंगाई पर दबाव निकट भविष्य में भी बना रह सकता है।

खुदरा बाजारों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में टमाटर 50 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। कुछ महानगरों में अच्छी गुणवत्ता वाला टमाटर इससे भी अधिक कीमत पर उपलब्ध है। ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म पर भी टमाटर की कीमतें 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच पहुंच चुकी हैं। कुछ सप्ताह पहले तक अपेक्षाकृत सस्ता मिलने वाला टमाटर अब आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है।

प्याज की कीमतों में भी लगातार तेजी बनी हुई है। खुदरा बाजारों में सामान्य प्याज 40 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। नासिक से आने वाली बेहतर गुणवत्ता की प्याज की कीमत इससे भी अधिक दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि पुराना स्टॉक सीमित रह गया है और नई फसल की उपलब्धता अपेक्षा से कम होने के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो आगामी महीनों में प्याज की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

आलू, जिसे आमतौर पर सबसे स्थिर कीमत वाली सब्जी माना जाता है, वह भी महंगाई से अछूता नहीं रहा। विभिन्न राज्यों में खुदरा बाजारों में आलू 15 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। ऑनलाइन बिक्री मंचों पर भी इसकी कीमतें लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। परिवहन लागत और भंडारण खर्च बढ़ने का असर भी इसकी कीमतों में दिखाई दे रहा है।

महंगाई का असर केवल सब्जियों तक सीमित नहीं है। चावल, गेहूं, दालों और खाद्य तेलों के दाम भी धीरे-धीरे ऊपर जा रहे हैं। खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खरीफ सीजन में वर्षा सामान्य से कम रहती है, तो धान, दलहन और तिलहन की पैदावार प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर आने वाले महीनों में बाजार की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ेगा। यही वजह है कि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों आगामी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जून के पहले 18 दिनों में मूंगफली तेल की कीमतों में 1.2 प्रतिशत, सरसों और सूरजमुखी तेल में 1.1-1.1 प्रतिशत तथा चावल की कीमतों में 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा मूंग दाल, चना दाल, गेहूं और अरहर दाल की कीमतों में भी मामूली लेकिन लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे स्तर की यह वृद्धि यदि लगातार जारी रहती है तो अगले कुछ महीनों में उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा।

महंगाई बढ़ने के पीछे केवल मौसम ही जिम्मेदार नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादों की ढुलाई महंगी हो जाती है। जब परिवहन खर्च बढ़ता है तो उसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाली बाधाएं भी खाद्य वस्तुओं की लागत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मौसम वैज्ञानिकों ने भी अल नीनो जैसी परिस्थितियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। अल नीनो का प्रभाव कई बार मानसून की तीव्रता और वितरण को प्रभावित करता है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो धान, दालें और तिलहन जैसी फसलें प्रभावित होती हैं और बाजार में उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। इसका परिणाम कीमतों में तेजी के रूप में सामने आता है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खाद्य महंगाई का प्रभाव सबसे अधिक निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर पड़ता है। इन परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। जब सब्जियों, अनाज और दालों की कीमतें एक साथ बढ़ती हैं तो घरेलू बजट असंतुलित हो जाता है। कई परिवारों को अपनी खपत में कटौती करनी पड़ती है या अन्य जरूरी खर्चों को टालना पड़ता है।

कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून सामान्य हो जाता है और वर्षा संतोषजनक रहती है, तो स्थिति में कुछ सुधार संभव है। पर्याप्त वर्षा होने से खरीफ फसलों की बुआई तेज होगी, उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में आपूर्ति बेहतर होने से कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि यदि वर्षा में और देरी होती है या उसका वितरण असमान रहता है तो खाद्य महंगाई की चुनौती और गंभीर हो सकती है।

सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी पर रोक लगाने और जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक का उपयोग करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों के साथ समन्वय बनाकर प्रमुख कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुचारु रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर कुछ हद तक कम किया जा सके।

फिलहाल स्थिति यही संकेत दे रही है कि आम लोगों की रसोई पर महंगाई का दबाव निकट भविष्य में आसानी से कम होने वाला नहीं है। मौसम की अनिश्चितता, वैश्विक हालात और कृषि उत्पादन से जुड़ी चुनौतियां आने वाले महीनों में खाद्य बाजार की दिशा तय करेंगी।

न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर 'आप' नेता प्रवीण राम के नेतृत्व में आशा वर्कर बहनों और आशा फैसिलिटेटर बहनों ने संघर्ष का आगाज किया, जिसमें गुजरात आशा यूनियन की पिंकीबेन परमार ने भी समर्थन दिया

▸▸ गिर सोमनाथ में 'आप' नेता प्रवीण राम के नेतृत्व में आशा बहनों और आशा फैसिलिटेटर बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई आशा यूनियन तथा गुजरात आशा वर्कर यूनियन के लेटरपैड पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

▸▸ कल से गिर सोमनाथ जिले की आशा और फैसिलिटेटर बहनें हड़ताल पर जाएंगी

▸▸ आशा बहनें और फैसिलिटेटर बहनें पोलियो अभियान का बहिष्कार करेंगी

▸▸ पूरे जिले से 'आप' नेता प्रवीण राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आशा बहनें उपस्थित रहीं तथा इस अवसर पर आशा बहनों की नेता पिंकीबेन परमार भी उपस्थित रहीं

▸▸ पूरे गुजरात की आशा बहनों को पिछले 4 महीनों से वेतन का भुगतान ही नहीं किया गया है

▸▸ इतनी महंगाई में आशा बहनों और फैसिलिटेटर बहनों को केवल 75 से 100 रुपये का ही भुगतान किया जाता है

अहमदाबाद/गिर सोमनाथ/गुजरातः गिर सोमनाथ में आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम के नेतृत्व में आशा बहनों और आशा फैसिलिटेटर बहनों ने न्यूनतम वेतन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष का आगाज किया। इस कार्यक्रम में गुजरात आशा यूनियन की नेता पिंकीबेन परमार भी उपस्थित रहीं और उन्होंने समर्थन की घोषणा की। आशा बहनों और फैसिलिटेटर बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई आशा यूनियन तथा गुजरात आशा वर्कर यूनियन के लेटरपैड पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर घोषणा की गई कि कल से गिर सोमनाथ जिले की आशा और फैसिलिटेटर बहनें हड़ताल पर उतरेंगी तथा पोलियो अभियान का भी बहिष्कार करेंगी। कार्यक्रम में पूरे जिले से बड़ी संख्या में आशा बहनें उपस्थित रहीं। आशा बहनों का आरोप है कि पूरे गुजरात में पिछले चार महीनों से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और वर्तमान महंगाई में केवल 75 से 100 तक का भुगतान किया जाता है, जिससे उनके परिवार का पालन-पोषण करना कठिन हो गया है। इसलिए सरकार से तत्काल उनकी मांगों को स्वीकार करने, उचित वेतन देने और बकाया भुगतान करने की मांग की गई।

इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने कहा कि आज गिर सोमनाथ कलेक्टर कार्यालय में जिले की आशा वर्कर बहनों और आशा वर्कर फैसिलिटेटर बहनों के मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया है। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार गिर सोमनाथ जिले और पूरे गुजरात में पिछले चार-पांच महीनों से बहनों को जो इंसेंटिव दिया जाता है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही बहनों से कुछ कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। PMMVI का भुगतान वर्ष 2023 से नहीं किया गया है। अभी पोलियो टीकाकरण का समय आता है और यदि पोलियो उन्मूलन में किसी का सबसे बड़ा योगदान है, तो वह आशा वर्कर बहनों और फैसिलिटेटर बहनों का है। लेकिन उन्हें अत्यंत कम वेतन दिया जाता है। वर्षों से ये बहनें न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और इन सभी बहनों ने निर्णय लिया है कि आने वाले बुधवार तक एक सप्ताह की हड़ताल घोषित की गई है। बुधवार को बहनें तय करेंगी कि कितने मुद्दों का संतोषजनक समाधान हुआ है या प्रशासन की ओर से कोई अपील आई है या नहीं, उसके बाद बुधवार को निर्णय लिया जाएगा। इसलिए अगले बुधवार तक हड़ताल रहेगी और पोलियो अभियान का बहिष्कार किया गया है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन सभी मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाए।

भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी मुठभेड़ ने बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पुलिस का हिसाब-किताब अनुशासन की जंजीरों से बंधा होता है। हर पुलिस स्टेशन में एक खूबसूरत नारा लिखा होता है, "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?" यानी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले ही जान सकते हैं कि इस नारे का असल मतलब क्या है। क्योंकि जनता का पुलिस पर भरोसा खत्म हो चुका है।

इसी सिलसिले में भाजपा ने बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता के "फर्जी मुठभेड़" मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुर्खियों में ला दिया है। यह मामला बिहार पुलिस के साथ मुठभेड़ में 26 वर्षीय भारत भूषण तिवारी की मौत का है, जिसने राज्य में हंगामा मचा दिया है। भोजपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र के बिलौती गांव के निवासी तिवारी बाढ़, नदी कटाव और विस्थापन जैसे मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाते रहे थे। उनकी मौत 17 जून को हुई। भारत भूषण तिवारी का कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वे "मानसिक रूप से अस्थिर" प्रतीत होते थे। तिवारी ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए पुलिस को ऐसी कार्रवाई (मुठभेड़) नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम इस तरह देखें तो तिवारी की हत्या फर्जी मुठभेड़ में हुई। इसके अलावा, तिवारी दलित समुदाय के मुद्दों को उठा रहे थे। एक तरफ तो पुलिस ने दो अलग-अलग कारण बताए, जिसके चलते इस कथित मुठभेड़ की चर्चा हुई। रिपोर्ट के अनुसार, 16 जून को जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि शाहपुर पुलिस स्टेशन के पास हथियार लेकर घूम रहे एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी। बाद में पुलिस ने बताया कि वह वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर था। यह भी कहा गया कि उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसके पास से हथियार बरामद करने के भी प्रयास जारी हैं।

हालांकि, अगले दिन, जब कथित फर्जी मुठभेड़ हुई, तो पुलिस ने एक और बयान जारी कर दावा किया कि उन्होंने भोजपुर एसटीएफ टीम के सहयोग से तिवारी को आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाया था। लेकिन तिवारी लगातार अपनी पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग करता रहा। पुलिस को अपनी जान और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए, पुलिस ने तिवारी के करीब जाने की कोशिश की और तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में, पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में और जनता की सुरक्षा के लिए फायरिंग की। पैर में गोली लगने से तिवारी की पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में इलाज के दौरान मौत हो गई। जब लोग कहते हैं कि मृतक तिवारी को वीडियो में पुलिस के सामने पिस्तौल फेंककर आत्मसमर्पण करते देखा गया था, तो पुलिस ने गोली क्यों चलाई? इस प्रकार, तिवारी के परिवार सहित बिहार के सभी विपक्षी दल अब इस मामले में बिहार की भाजपा सरकार से न्याय की मांग करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सतर्क हो गए हैं।

महाराष्ट्र एफडीए का आदेशः होटलों और रेस्तरां में ग्राहकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश भर के अधिकांश होटलों और रेस्तरांओं ने मुफ्त स्वच्छ पानी देना बंद कर दिया है और अब बिल में ठंडे पानी की बोतलें अनिवार्य रूप से जोड़ दी गई हैं। बुधवार को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने एक आदेश जारी कर सभी होटलों, रेस्तरांओं और खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों को ग्राहकों को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराने और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है कि ग्राहकों से पीने के पानी के लिए अलग से शुल्क लिया जा रहा है।

आदेश में कहा गया है, "ग्राहकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना संगठन की जिम्मेदारी है। यदि ग्राहक पैकेटबंद या बोतलबंद पानी पर जोर देता है, तो उससे शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन यदि वह पीने योग्य अच्छा पानी मांगता है, तो उससे इसके लिए शुल्क लेना उचित नहीं है।" बुधवार को जारी एफडीए के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेजों पर पानी की बोतलें रखने के लिए शुल्क लेने की तरकीब अब नहीं चलेगी। यानी, होटलों और रेस्तरां को ग्राहकों को मुफ्त में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना होगा।

संपादकीय

सूखे की आहट

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कमजोर रहने की चिंताओं के बीच देश के कृषि क्षेत्र के सामने सूखे की चुनौती पैदा होने की आशंका बलवती हुई है। हाल-फिलहाल बारिश में चालीस से छियालीस प्रतिशत की कमी मापी गई है। देश के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो जुलाई तक मानसून की सक्रियता कम रहने के अनुमान के कारण खरीफ की फसल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने कम बारिश वाले 315 जिलों में से 111 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे की दृष्टि से ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं। जो आसन्न संकट की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मॉनसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मॉनसून में देरी या कम बारिश होने का सीधा असर फसल की बुवाई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीणों की आय और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में यदि जुलाई व अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन कर सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है। साथ ही कोशिश है कि किसानों के लिये बीज-उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। देश में दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी सामान्य उत्पादन दे सकती हैं। सुखद ही है कि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये रियल-टाइम सलाह किसानों को देकर सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सूखे से मुकाबले का मतलब है कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है।

आज जरूरत इस बात की है कि सूखे की आशंका के बीच जल संकट से मुकाबले के लिये एक प्रभावी समग्र नीति बने। समय-समय पर इन नीतियों में सुधार किया जाए। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन संकट के दौर में मानसून के व्यवहार में अनिश्चितता के बीच खेती की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिये व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके लिये जरूरी है कि सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा का विस्तार, जल निकायों के पुनरुद्धार, भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने और जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हों। हम मौसम के बदलते मिजाज पर हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। हमें किसानों को आर्थिक संकट से उबारने को अपनी वरीयता सूची में शामिल करना चाहिए। विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की रक्षा के लिये बीमा कवरेज अभी भी ज्यादा प्रभावी नहीं है। किसानों को फसलों को क्षति पहुंचने पर मुआवजा लेने के बारे में व्यावहारिक जानकारी अक्सर कम ही होती है। वैसे तो देश में अनाज का पर्याप्त भंडारण है और आपातकालीन व्यवस्था के चलते देश की खाद्य सुरक्षा को तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हमें लाखों किसानों का जीविका संरक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में मौसम के मिजाज में होने वाला बदलाव अब कभी-कभार की बाधा नहीं रही, बल्कि बार-बार होने वाली सच्चाई बन गया है। मानसून के व्यवहार में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए देश के नीति-निर्माताओं को खेती संरक्षण के लिये एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो मौसम के बदलावों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सके। तभी हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सही तरीके से सामना कर सकेंगे। साथ ही हमें देश में पानी के सदुपयोग की दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। देश में जलाशयों के जल का किफायती उपयोग हो। निस्संदेह, कम बारिश से केवल किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती है, सूखे में खाद्यान्न की उत्पादकता घटने पर अनाज महंगा होने से आम आदमी का जीवन भी बाधित होता है। जिससे किसान की ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

आधुनिक तकनीक और मजबूत इरादे रोकेंगे घुसपैठ

" गृह मंत्रालय देश की 6,000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक शक्तिशाली ग्रिड बनायेगा। इसमें निगरानी रखने वाली आधुनिकतम प्रणालियां जैसे ड्रोन, रडार, उच्च शक्ति वाले कैमरे और मॉनिटरिंग करने वाली अन्य टेक्नोलॉजी होगी ताकि सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को बेहतर ढंग से बढ़ाया जा सके।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बहुत लंबी हैं और वे छह देशों से लगी हुई हैं। इनमें कई जगहों पर सेना तथा अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा है। जैसे कि पाकिस्तान से लगती सीमा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है और इसकी देखभाल के लिए मुख्य तौर पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है और जहां जंग जैसे हालात हैं वहां भारतीय सेना अपनी पूरी क्षमता के साथ तैनात है । लेकिन पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश सीमा एक सिरदर्द बन गई है क्योंकि वहां से बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने लगी थी। लाखों की तादाद में घुसपैठिये भारत में खासकर बंगाल और असम में आ घुसे। इन्हें रोकना एक चुनौती रही क्योंकि भारत-बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी यानी 4096 किलोमीटर की है जो पांच राज्यों को छूती है। इनमें कई जगहों पर न तो बाड़ है और न ही तार। इसका फायदा उठाकर घुसपैठिये भारत में आसानी से घुसते रहे हैं।

अब जबकि बंगाल में भाजपा आ गई है तो सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज हो गया है। बंगाल की तत्कालीन सरकार ने घुसपैठियों को रोकने तथा देश की रक्षा के इस महती प्रयास में जरा भी साथ नहीं दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि उन इलाकों में स्थानीय लोगों की तुलना में बाहरी लोग खासकर बंगाल में बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं। जनसंख्या में यह भारी बदलाव देश की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए खतरा बनकर उभरा है। घुसपैठियों के आने से कई तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं और एक खास समुदाय के लोगों की आबादी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है।

दरअसल, जनसंख्या में यह बदलाव स्वाभाविक नहीं है बल्कि जानबूझकर और एक रणनीति के तहत अवैध तरीके से हुआ है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस मुद्दे को गृह मंत्रालय ने प्रमुखता से न केवल उठाया बल्कि इसके समाधान के लिए भी बड़े कदमों की घोषणा की तथा उन्हें कार्यान्वित करवाना शुरू कर दिया है। इसके लिए पारंपरिक तरीकों की बजाय डिजिटल टेक्नोलॉजी और कुशल मैनेजमेंट प्रणाली का सहारा लिया जायेगा ताकि अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों को निकाल बाहर किया जाये।

इसी कड़ी में देश की सीमाओं को पक्का करने के लिए घोषणा की गई है कि एक देशव्यापी स्मार्ट बोर्डर प्लान परियोजना एक वर्ष में आरंभ की जायेगी। इसके जरिये सीमा सुरक्षा को न केवल मजबूत किया जायेगा बल्कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ताकि सीमा पार से घुसपैठ पर अंकुश लगे। इसके तहत गृह मंत्रालय देश की 6,000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक शक्तिशाली ग्रिड बनायेगा। इसमें निगरानी रखने वाली आधुनिकतम प्रणालियां जैसे ड्रोन, रडार, उच्च शक्ति वाले कैमरे और मॉनिटरिंग करने वाली अन्य टेक्नोलॉजी होगी ताकि सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को बेहतर ढंग से बढ़ाया जा सके। इनकी मदद से दूर बैठकर ही जाना जा सकेगा कि कहां की सीमा पर खतरा है या कहां से घुसपैठ हो रही है। इससे हमारे सशस्त्र बलों को बहुत सुविधा होगी। उनके दिन-रात गश्त के बावजूद घुसपैठिये अपना काम कर जाते हैं लेकिन अब यह नहीं हो सकेगा। आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन आकाश से आसानी से निगरानी कर सकेंगे और रडार चेतावनी देंगे।

बंगाल की नई सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक के पास 120 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल को दे दी है। वहां की पिछली सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद उस जगह को देने से इनकार कर दिया था। इस जगह को सिलीगुड़ी कॉरिडर कहा जाता है और शत्रु देश इसमें भारी घुसपैठ करके भारत के पूर्वोत्तर को उससे अलग कर सकता है। बांग्लादेश की भारत से लंबी सीमा में से अभी 600 किलोमीटर बिना बाड़ या किसी तरह के फेंस की थी। इस गैप को बंद करने के पीछे सीमा में अवैध घुसपैठ, तस्करी, पशुओं की चोरी, अवैध धंधे वगैरह पर अंकुश लगाना है। कुछ इलाकों में तो बांग्लादेश के निवासियों ने बाड़ लगाने के काम का पुरजोर विरोध भी किया और वहां के अर्धसैनिक बल ने भी उनका साथ दिया लेकिन सीमा सुरक्षा बल की सख्ती के कारण उनकी एक न चली और कंटीली तारें लगाने का काम जोर-शोर से चल रहा है। सरकार ने इसके लिए पर्याप्त फंड की भी व्यवस्था की है ताकि युद्धस्तर पर हो रहा काम रुकने न पाये।

पिछले महीने के अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने देश में अवैध घुसपैठ और अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की। ऐसा करके उन्होंने इस मामले को राजनीतिक न रहने देने की बजाय एक संस्थागत रूप में बदल दिया। यह कमेटी भारत में रह रहे हर अवैध घुसपैठिये की पहचान करेगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो भारत में रह रहे हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर करेंगे। इस कदम से अवैध घुसपैठ को रोकने के काम को कानूनी और संस्थागत सहारा मिलेगा। यह कमेटी देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ तथा अप्राकृतिक कारणों से हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेगी। कमेटी के सदस्य क्षेत्रीय और जिला स्तर पर इस बात का अध्ययन करेंगे कि अवैध घुसपैठ के कारण वहां की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई और उसका गवर्नेंस, जन सेवाओं तथा सामाजिक स्थिरता पर क्या असर पड़ा या पड़ रहा है। यह कमेटी समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके तुरंत बाद बाद एक राष्ट्रीय एक्शन योजना बनाई जायेगी।

प्रेरणा

वाणी की पवित्रता का अमूल्य आदर्श

मनुष्य को प्रकृति ने अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं, परंतु उनमें सबसे प्रभावशाली शक्ति उसकी वाणी है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे व्यक्ति के संस्कार, विचार, चरित्र और व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। एक मधुर शब्द टूटे हुए मन को जोड़ सकता है, जबकि एक कटु शब्द वर्षों पुराने संबंधों को भी क्षणभर में नष्ट कर सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वाणी की शुद्धता और शब्दों की मर्यादा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे ऋषि-मुनियों ने सदैव यह शिक्षा दी कि मनुष्य को केवल अच्छे कर्म ही नहीं करने चाहिए, बल्कि उसके मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र और हितकारी होने चाहिए।

भारतीयता के महान संवाहक और शिक्षा, संस्कृति तथा राष्ट्रभक्ति के प्रतीक महामना पंडित मदनमोहन मालवीय का जीवन इसी आदर्श का उत्कृष्ट उदाहरण था। वे केवल विचारों से ही नहीं, बल्कि व्यवहार से भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीते थे। उनके जीवन का प्रत्येक कार्य इस बात का प्रमाण था कि महानता केवल बड़े पदों या उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि छोटी-छोटी बातों में भी आदर्शों का पालन करने से प्राप्त होती है।

एक बार की बात है। महामना मालवीय जी बंबई प्रवास पर थे और उद्योगपति रामेश्वरदास बिरला के निवास पर ठहरे हुए थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर प्रसिद्ध विद्वान पंडित रमापति मिश्र उनसे मिलने पहुँचे। दोनों विद्वानों के बीच अनेक विषयों पर चर्चा होने लगी। बातचीत का क्रम आगे बढ़ा तो विषय क्रोध पर आ गया। यह विषय सदैव से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होती है।

चर्चा के दौरान पंडित रमापति मिश्र ने आत्मविश्वास से कहा, "मालवीय जी, मैं तो क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूँ। आप चाहें तो मुझे सौ गालियाँ देकर देख लीजिए, मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आएगा।" यह सुनकर सामान्य व्यक्ति शायद उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करता, किंतु महामना मालवीय की दृष्टि कहीं अधिक गहरी थी। वे मुस्कराए और अत्यंत विनम्रता से बोले, "पंडित जी, क्षमा करें। यह मुझसे संभव नहीं होगा। आपकी सहनशीलता की परीक्षा तो एक सौ गालियाँ देने के बाद होगी, पर मेरा मुख तो एक ही गाली देने पर मैला हो जाएगा।"

मालवीय जी का यह उत्तर केवल एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के गहन दर्शन का सार था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सामने वाले की परीक्षा कैसे ली जाए। उन्होंने पहले अपने चरित्र और अपनी वाणी की पवित्रता को महत्व दिया। उनके लिए किसी को अपशब्द कहना, चाहे परीक्षा लेने के लिए ही क्यों न हो, स्वयं अपने व्यक्तित्व को कलुषित करने के समान था। यह दृष्टिकोण बताता है कि सच्चा सज्जन व्यक्ति केवल दूसरों के व्यवहार पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने आचरण की शुद्धता को भी सर्वोपरि मानता है।

आज के समय में यह प्रसंग और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आधुनिक जीवन में लोग छोटी-छोटी बातों पर कटु शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। सोशल मीडिया हो, पारिवारिक संबंध हों या सार्वजनिक जीवन, अनेक स्थानों पर भाषा की मर्यादा टूटती दिखाई देती है। लोग यह सोचकर कठोर शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले को कितना बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि अपशब्द बोलने से सबसे पहले उनकी अपनी वाणी दूषित होती है। जिस प्रकार गंदगी को हाथ लगाने से हाथ भी मैले हो जाते हैं, उसी प्रकार कटु और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से बोलने वाले का व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है।

भारतीय दर्शन में वाणी को देवी सरस्वती का स्वरूप माना गया है। इसलिए कहा गया है कि शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या धन से नहीं, बल्कि उसकी भाषा और व्यवहार से होती है। एक विनम्र व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संयमित भाषा का प्रयोग करता है, जबकि असंयमी व्यक्ति छोटी बातों पर भी मर्यादा खो बैठता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों ने सदैव मधुर वाणी को सबसे बड़ा आभूषण बताया है।

कबीरदास जी ने भी कहा है—

"ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होय॥"

इस दोहे का अर्थ है कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अहंकार समाप्त हो जाए, जो दूसरों को शांति और सुख प्रदान करे तथा स्वयं को भी आनंद दे। वास्तव में मधुर वाणी केवल दूसरों को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि स्वयं के मन को भी शांत और निर्मल बनाती है।

मालवीय जी के उत्तर में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन में केवल बुरे कार्यों से बचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कार्यों के साधनों से भी बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह किसी की परीक्षा लेने के लिए झूठ बोलेगा या अपमान करेगा, तो भी वह गलत ही माना जाएगा। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक है। यही भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है।

आज समाज में अनेक विवाद केवल इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। क्षणिक आवेश में कहे गए शब्द कभी-कभी ऐसे घाव दे जाते हैं जो वर्षों तक नहीं भरते। तलवार से लगे घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन कटु वचनों से लगे घाव अक्सर जीवनभर स्मृति में बने रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे और हर परिस्थिति में शब्दों की गरिमा बनाए रखे।

महामना मालवीय का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि वास्तविक महानता दूसरों को परखने में नहीं, बल्कि स्वयं को मर्यादित रखने में है। यदि हम अपने शब्दों को पवित्र बनाए रखें, तो हमारे संबंध मजबूत होंगे, समाज में सौहार्द बढ़ेगा और हमारा व्यक्तित्व भी सम्मान का पात्र बनेगा। शब्दों की शुचिता केवल भाषा की सुंदरता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता का भी प्रतीक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में वाणी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्दों का प्रभाव दूर तक जाता है और वे हमारे चरित्र की पहचान बन जाते हैं। इसलिए हमें सदैव ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सत्य, मधुर, हितकारी और मर्यादित हों। महामना मालवीय का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपनी वाणी को इतना निर्मल बनाएँ कि उससे किसी का अपमान नहीं, बल्कि सम्मान बढ़े; किसी का हृदय न टूटे, बल्कि जुड़ जाए। यही शब्दों की वास्तविक शुचिता है और यही भारतीय संस्कृति का अमर संदेश भी।

Passport, Aadhar, PAN, Voter Card अगर Indian Citizenship का सबूत नहीं हैं तो क्या है भारतीय नागरिकता का प्रमाण?

नई दिल्ली में पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए एक बयान ने देशभर में नागरिकता से जुड़ी बहस को फिर तेज कर दिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज है और इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट विदेश में भारतीयों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करता है, लेकिन यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और लोग यह पूछने लगे कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो फिर भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज मान्य है? विदेश मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण भले ही पहले के न्यायालयीय निर्णयों के अनुरूप माना जा रहा हो, लेकिन इसका समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल हाल के वर्षों में नागरिकता को लेकर देश में लगातार बहस चल रही है, विशेषकर निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में। बिहार में इसी मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की पीठ ने भी कहा था कि आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं।

अब विदेश मंत्रालय के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। एक उपयोगकर्ता ने भारतीय पासपोर्ट की तस्वीर साझा करते हुए पूछा कि जब उसमें राष्ट्रीयता भारतीय लिखी हुई है, तो फिर उसे नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा? कई अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट, आधार और मतदाता पहचान पत्र भी पर्याप्त नहीं हैं, तो आखिर नागरिकता सिद्ध करने का आधार क्या होगा। कुछ लोगों ने इस बयान को विचित्र और भ्रम पैदा करने वाला बताया। उनका कहना था कि विदेशों में भारतीय होने की पहचान देने वाला दस्तावेज यदि देश के भीतर ही मान्य नहीं माना जाएगा, तो इससे लोगों में असमंजस और बढ़ेगा।

इस विवाद के बीच सरकार की प्रेस सूचना इकाई का वर्ष 2019 का एक पुराना प्रश्नोत्तर भी चर्चा में आ गया। राष्ट्रीय नागरिक पंजी से जुड़े उस प्रश्नोत्तर में कहा गया था कि जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता साबित की जा सकती है, हालांकि ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। यही कारण है कि अब लोगों के बीच यह भ्रम और गहरा गया है कि आखिर कौन-सा दस्तावेज कानूनी रूप से नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा?

इस बीच, विपक्षी दलों ने भी विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर कौन-सा दस्तावेज है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि किसी बूथ स्तर के अधिकारी को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह हो जाए, तो उसे मतदान के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आज के समय में भारतीय नागरिकता का प्रमाण शायद केवल यह रह गया है कि कोई व्यक्ति हिंदू हो और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हो।

शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने विदेश मंत्रालय के बयान को हास्यास्पद बताते हुए पूछा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस आखिर किस बात का सत्यापन करती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारत गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट जारी करता है। ठाकरे ने आशंका जताई कि इस तरह के बयान से अन्य देशों के मन में भी संदेह पैदा हो सकता है कि कहीं भारतीय पासपोर्ट गैर भारतीयों को तो नहीं दिया जाता। उन्होंने विदेश नीति को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि इस प्रकार के बयान से देश की छवि प्रभावित हो सकती है।

कांग्रेस की केरल इकाई ने भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि आधार केवल एक कार्ड है, पैन खाना पकाने के लिए है, मतदाता पहचान पत्र केवल दिखाने के लिए है और आयकर विवरणी केवल आय लौटाने के लिए है। पार्टी ने इस पूरे विवाद को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

उधर, विदेश मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि पासपोर्ट जारी करने से पहले विभिन्न सरकारी एजेंसियों के दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत जांच की जाती है। मंत्रालय ने नए चिप आधारित ई पासपोर्ट की विशेषताओं का भी उल्लेख किया, जिनमें जैविक पहचान संबंधी सूचनाएं शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की स्वीकार्यता बढ़ाना और धोखाधड़ी की आशंका को कम करना है। हालांकि विदेश मंत्रालय की कानूनी व्याख्या स्पष्ट है, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर देश में नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर व्यापक बहस को जन्म दे दिया है।

अभियान

मोक्ष की राह पर चलती दिव्य यात्रा: क्यों करोड़ों श्रद्धालुओं को पुरी की रथयात्रा का रहता है इंतजार

भारत को यदि आस्था और अध्यात्म की भूमि कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ के पर्व, उत्सव और तीर्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को समझने, आत्मा को जागृत करने और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी हैं। इन्हीं महान परंपराओं में एक है भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा, जो हर वर्ष ओडिशा के पुरी नगर में आयोजित होती है। यह उत्सव केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास, समानता और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। लाखों श्रद्धालु वर्षभर इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर सकें और उस आध्यात्मिक अनुभूति का हिस्सा बन सकें जो सदियों से लोगों के जीवन को आलोकित करती आई है।

पुरी का नाम सुनते ही मन में समुद्र की लहरों के बीच स्थित भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर की छवि उभर आती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के चार प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। किंतु जगन्नाथ संस्कृति की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं रहते। वर्ष में एक बार वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें यह अनुभव कराते हैं कि ईश्वर किसी दूरी या सीमा में बंधे नहीं हैं।

रथयात्रा का आरंभ होते ही पुरी का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। सड़कों पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों की घंटियाँ, शंखध्वनि, हरिनाम संकीर्तन और जय जगन्नाथ के गगनभेदी उद्घोष वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा नगर किसी दिव्य लोक में परिवर्तित हो गया हो। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर विराजमान होकर मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।

गुंडिचा मंदिर का महत्व इस यात्रा में अत्यंत विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान वर्ष में एक बार अपनी मौसी के घर जाने की परंपरा निभाते हैं। यद्यपि यह कथा धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। यह संदेश है कि ईश्वर अपने भक्तों से दूर नहीं रहते, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बनकर उनके सुख-दुख में सहभागी होते हैं।

गुंडिचा मंदिर मुख्य जगन्नाथ मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दूरी भले ही कम दिखाई देती हो, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक प्रतीकात्मक यात्रा है। इसे आत्मा की यात्रा माना जाता है, जिसमें मनुष्य संसार की जटिलताओं से निकलकर ईश्वर की शरण में पहुँचने का प्रयास करता है। जब भगवान स्वयं इस मार्ग पर चलते हैं, तब वे भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में आध्यात्मिकता का मार्ग भी सभी के लिए खुला है।

रथयात्रा में प्रयुक्त होने वाले तीनों रथ अपने आप में अद्भुत होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ कहलाता है। इन रथों का निर्माण विशेष धार्मिक नियमों के अनुसार किया जाता है। हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं, जिनमें पारंपरिक शिल्पकला की झलक दिखाई देती है। हजारों कारीगर अपनी कला और श्रद्धा से इन्हें तैयार करते हैं। जब ये विशाल रथ सड़कों पर आगे बढ़ते हैं, तब उनका दृश्य भक्तों के लिए किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं होता।

रथयात्रा का सबसे प्रेरणादायक पक्ष यह है कि इसमें समाज का हर वर्ग भाग लेता है। चाहे कोई धनी हो या निर्धन, विद्वान हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक साथ रथ की रस्सी खींचते हैं। यहाँ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव दिखाई नहीं देता। यह दृश्य भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को जीवंत कर देता है जिसमें समस्त मानवता को एक परिवार माना गया है। भगवान के समक्ष सभी समान हैं और यही रथयात्रा का सबसे बड़ा सामाजिक संदेश है।

धार्मिक मान्यता है कि रथयात्रा के दौरान भगवान के दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अनेक श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि भगवान के रथ की एक झलक भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यही कारण है कि लाखों लोग घंटों तक धूप और भीड़ की परवाह किए बिना केवल दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक तृप्ति का अवसर होता है।

भारतीय दर्शन में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के अज्ञान, अहंकार, लोभ और मोह से मुक्ति भी है। रथयात्रा इसी गहन सत्य की ओर संकेत करती है। जब भक्त भगवान के रथ के साथ चलते हैं, तो वे प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।

गुंडिचा मंदिर में भगवान का कुछ दिनों तक निवास करना भी विशेष अर्थ रखता है। यह अवधि भक्तों को यह संदेश देती है कि ईश्वर केवल क्षणिक रूप से नहीं, बल्कि सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उनका प्रेम और संरक्षण निरंतर उपलब्ध है। आवश्यकता केवल श्रद्धा और विश्वास की है। इसी कारण जो श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, वे गुंडिचा मंदिर के दर्शन को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं।

आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि गुंडिचा मंदिर मानव हृदय का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान अपने मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन को शुद्ध करता है तो उसके भीतर भी ईश्वर का वास हो सकता है। यह विचार जगन्नाथ परंपरा को केवल धार्मिक आयोजन से ऊपर उठाकर आत्मिक साधना का स्वरूप प्रदान करता है।

रथयात्रा का एक और विशेष संदेश है सेवा का। इस अवसर पर हजारों स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता करते हैं। भोजन वितरण, चिकित्सा सेवा, जल व्यवस्था और अन्य कार्यों में लोग निस्वार्थ भाव से योगदान देते हैं। यह भावना दर्शाती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानव सेवा में भी प्रकट होती है।

आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक इच्छाओं में उलझा हुआ है, तब जगन्नाथ रथयात्रा उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाती है। यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वर के साथ संबंध में है। भगवान का अपने सिंहासन से उतरकर जनता के बीच आना यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

रथयात्रा का दृश्य यह भी बताता है कि जीवन स्वयं एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी आनंद आता है, कभी कठिनाइयाँ। कभी सफलता मिलती है, कभी निराशा। किंतु यदि मनुष्य के जीवन में आस्था का दीपक जलता रहे, तो वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। भगवान जगन्नाथ का रथ इसी विश्वास और आशा का प्रतीक है जो लाखों लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है।

सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी प्राचीन काल में थी। तकनीक और आधुनिकता के इस दौर में भी जब रथयात्रा आरंभ होती है, तो करोड़ों लोगों की भावनाएँ उससे जुड़ जाती हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो लोगों को उनके सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक विरासत से जोड़ता है।

अंततः कहा जा सकता है कि पुरी की रथयात्रा और गुंडिचा मंदिर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की अनमोल धरोहर हैं। यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि अनुभव किए जाते हैं। वे अपने भक्तों के बीच आकर यह संदेश देते हैं कि प्रेम, भक्ति और विश्वास ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित होकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। उनके लिए यह केवल रथों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, विश्वास की विजय और मोक्ष की ओर बढ़ते कदमों का महापर्व है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

साक्षरता के रंग में ज्ञान का प्रवेश द्वार : शाला प्रवेशोत्सव-2026

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूरत के खटोदरा की नगर प्राथमिक शालाओं में बालवाटिका तथा कक्षा-1 के 373 नन्हे बच्चों का शाला प्रवेश कराया

प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों का उत्साहपूर्वक स्वागत कर रूमाल पर कुमकुम पगछाप कर स्मृति-चिह्न के रूप में भेंट किया गया

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

- विद्यार्थी 'घर के पुलिस' बनें, माता-पिता को हेलमेट पहने बिना बाहर न जाने देने के लिए आग्रह और जिद करें
- निजी विद्यालय छोड़कर सूरत के 4,708 विद्यार्थियों ने मनपा के सरकारी विद्यालयों पर विश्वास जताया

गांधीनगर : सूरत महानगर पालिका द्वारा 'प्रगति का शाला प्रवेशोत्सव एवं कन्या केळवणी महोत्सव-2026' अंतर्गत खटोदरा कॉलोनी स्थित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति-सूरत संचालित शाला क्रमांक 45, 46 व 275 में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने बालवाटिका तथा कक्षा-1 के 373 नन्हे बच्चों का कुमकुम तिलक कर उत्साहपूर्वक शाला में प्रवेश कराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विशेष स्नेहभाव के साथ अपने विशेष स्नेहभाव के साथ अपनी ओर से बच्चों को ड्रॉइंग बुक, कलर पेन बॉक्स सहित शैक्षणिक किट भेंट कर प्रोत्साहित किया।

नए प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों का भव्य स्वागत कर रूमाल पर कुमकुम के पगछाप कर स्मृति-चिह्न के रूप में उन्हें भेंट किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दशकों से अधिक की सफल यात्रा के बाद यह शाला प्रवेशोत्सव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महायज्ञ बन चुका है। बेटों के साथ बेटियाँ भी पढ़-लिखकर आगे बढ़ें और समाज, राज्य तथा देश का नाम रोशन करें; ऐसे सामूहिक प्रयास करने के लिए जरूरी है कि सभी आगे आएँ।

श्री संघवी ने कहा कि सूरत विशाल हृदय वाला शहर है, जहाँ प्रत्येक भाषा-भाषी परिवार को उसकी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके; इसके लिए महानगर

पालिका ने देश की छह भाषाओं गुजराती, मराठी, हिन्दी, उर्दू, ओडिया और अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय प्रारम्भ कर मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा मॉडल लागू किया है। वर्तमान में लगभग 1,99,186 विद्यार्थी मनपा विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में शिक्षकों को बुनियादी भूमिका निभानी है।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सूरत मनपा संचालित शालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है। इसका प्रमाण निजी विद्यालय छोड़कर सरकारी शालाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या है। निजी विद्यालयों से 4,708 विद्यार्थियों ने मनपा के सरकारी विद्यालयों पर विश्वास जताया है। इस वर्ष सूरत जिले में 21,113 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया है, जिनमें बालवाटिका के 9,028 नन्हे बच्चे शामिल हैं।

शिक्षा के साथ संस्कार तथा जीवन मूल्यों का सिंचन करने पर बल देते हुए श्री संघवी ने शिक्षकों एवं अभिभावकों से बच्चों को मोबाइल और केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर हँसते-खेलते सिखाने / पढ़ाने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वच्छता एवं सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि विद्यार्थियों को जागरूक बनकर परिवार के सदस्यों को भी स्वच्छता के प्रति जागृत कर घर, आँगन और मोहल्ले में स्वच्छता का आग्रह करना चाहिए। कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके।

उन्होंने परिवहन में सुरक्षा के महत्व को समझाते हुए विद्यार्थियों का 'घर के पुलिस' बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हमारे माता-पिता हेलमेट पहने बिना बाहर जा रहे हों, तो उन्हें रोकें और हेलमेट पहनने के लिए आग्रह और जिद करें, कारण कि माता-पिता का जीवन अमूल्य है और हमारी थोड़ी-सी लापरवाही जीवन को जोखिम में डाल देती है। उन्होंने साथ ही जनप्रतिनिधियों तथा विद्यालय स्टाफ को भी विद्यालय परिसर को ग्रीन व क्लीन रखने के लिए सतत सावधानी बरतने के निर्देश दिए, जिससे सूरत की शालाएँ आदर्श शैक्षणिक परिसर बनें।

इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन सूरत के संकल्प के साथ उप मुख्यमंत्री तथा महानुभावों के करकमलों से शाला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सभी ने यातायात नियमों का पालन करने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सतर्क रहने तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ग्रहण की।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मायाबेन मावाणी, मनपा आयुक्त श्री एम. नागराजन, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रभाई कापडिया, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भगीरथसिंह परमार, मनपा शासनाधिकारी श्री धर्मेश पटेल, पार्षद, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्य, सामाजिक अग्रणी, दाता, आचार्य, शिक्षक तथा बड़ी संख्या में अभिभावक एवं प्रवेश प्राप्त करने वाले नन्हे बच्चे उपस्थित रहे।

सूरत मनपा की शाला क्रमांक 45, 46 और 275 में बालवाटिका तथा कक्षा-1 के 373 नन्हे बच्चों ने शिक्षा पथ पर रखा पहला कदम

उधना दरवाजा के निकट, एपल अस्पताल के पीछे, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, खटोदरा कॉलोनी स्थित जयप्रकाश नारायण प्राथमिक विद्यालय क्रमांक-45 में बालवाटिका में 26 बालकों-24 बालिकाओं (कुल 50), कक्षा-1 में 43 बालकों-34 बालिकाओं (कुल 77), श्री मोतीभाई अमीन प्राथमिक शाला क्रमांक-46 में बालवाटिका में 27 बालकों-24 बालिकाओं (कुल 51) तथा कक्षा-1 में 48 बालकों-28 बालिकाओं (कुल 76) और अब्बास तैयबजी प्राथमिक शाला क्रमांक-275 में बालवाटिका में 13 बालकों-28 बालिकाओं (कुल 41) तथा कक्षा-1 में 29 बालकों-49 बालिकाओं (कुल 78) सहित कुल 373 नन्हे बच्चों ने शाला प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा के पथ पर अपना पहला कदम रखा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने वीजीआरसी से पूर्व वडोदरा के 12,902 उद्यमियों को 1,432 करोड़ रुपए की सहायता अर्पित की

- मेहसाणा, राजकोट और सूरत जोन की वीजीआरसी की तुलना में सर्वाधिक सहायता वडोदरा के उद्यमियों को दी गई
- गुजरात सरकार द्वारा घोषित की गई नई उद्योग नीति से देश-विदेश के उद्योगों का गुजरात की ओर आकर्षण बढ़ रहा है : श्री हर्ष संघवी
- उप मुख्यमंत्री ने उद्योगकारों से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में उत्साहपूर्वक सहभागी होने की अपील की

गांधीनगर : वडोदरा शहर में महीने के अंत में आयोजित होने वाली मध्य गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से पूर्व गुरुवार को उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के 9,171 सहित कुल 12,902 उद्यमियों को 1,432.41 करोड़ रुपए की सहायता अर्पित की। साथ ही; उन्होंने उद्योगकारों तथा औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के उदार भाव से त्वरित समाधान की तत्परता दर्शाई।

वाइब्रेंट गुजरात की चौथी रीजनल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में उद्योगकारों के विभिन्न संगठनों तथा प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में श्री संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के विजन से गुजरात सरकार द्वारा घोषित की गई नई उद्योग नीति से देश और विदेश के उद्योगों का गुजरात की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। राज्य में नवीनतम उद्योग आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गुजरात के व्यापारी और उद्योगपति हमेशा नवीनतम प्रयोग करने में सफल रहे हैं। व्यापार एवं उद्योग गुजरातियों के लहु में बहता है और वे हमेशा देश और दुनिया को कुछ न कुछ नया देते रहते हैं। यहाँ से निर्यात में वृद्धि होती रहती है, जो इन बातों का प्रमाण है। राज्य सरकार भी व्यापार-उद्योग के अनुकूल नीति अपनाती रही है।

श्री संघवी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों तथा उद्योगकारों की समस्याओं का निरंतर समाधान भी किया जा है। इसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है। कोई भी समस्या हो, उसे विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

वडोदरा में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में उत्साहपूर्वक भाग लेने का निमंत्रण देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक मेहसाणा, राजकोट और सूरत में क्षेत्रीय संमेलन आयोजित हुए हैं। हर समिट से पूर्व राज्य सरकार द्वारा देय सहायता का वितरण किया जाता है।

उन्होंने बताया कि उद्योगकारों को मेहसाणा में 905 करोड़ रुपए, राजकोट में 956 करोड़ रुपए तथा सूरत में 1,344 करोड़ रुपए की सहायता का वितरण किया गया है। इन तीनों अंचलों की तुलना में वडोदरा में सर्वाधिक 1,432 करोड़ रुपए की सहायता वितरित हुई, जो वडोदरा में औद्योगिक विकास को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई विभाग अंतर्गत 9,171 लाभार्थियों को 402.58 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल योजना अंतर्गत 3,490 लाभार्थियों को 471.62 करोड़ रुपए, लार्ज इंडस्ट्रीज अंतर्गत 213 लाभार्थियों को 523.15 करोड़ रुपए तथा अन्य विभिन्न योजना अंतर्गत 34 लाभार्थियों को 35.06 करोड़ रुपए की सहायता एवं लाभ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के करकमलों से दिए गए।

बैठक के दौरान इंडेक्स-बी के प्रबंध निदेशक श्री केयुर संपत ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा देने के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया।

इस बैठक में राज्य मंत्री श्रीमती मनीषाबेन वकील, सांसद डॉ. हेमांगभाई जोशी, विधायक श्री चैतन्यभाई देसाई, अग्रणी श्री जयप्रकाशभाई सोनी, पुलिस आयुक्त श्री नरसिम्हा कोमर, सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार, वरिष्ठ अधिकारी श्री पी. स्वरूप, श्री पी. भारती, श्री संदीप सिंह, मनपा आयुक्त श्री अरुण महेश बाबू, जिला कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक सम्पन्न

पश्चिम रेलवे की क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 25 जून, 2026 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय की ई-पत्रिका 'ई-राजहंस' के 63वें अंक का विमोचन महाप्रबंधक महोदय के कर-कमलों से किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी की जयंती भी मनाई गई। उनके जीवन के संक्षिप्त परिचय से सदस्यों को अवगत कराया गया और उनकी एक प्रसिद्ध कविता 'नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है' का गायन द्वारा प्रस्तुतिकरण भी किया गया।

राजभाषा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने कहा कि राजभाषा हिंदी भारत की अस्मिता है। जो भी नागरिक अपनी राष्ट्रीयता को संकीर्णता से देखेगा उसे देश में अनेक भिन्नताएं दिखेंगी, लेकिन जो भिन्नताओं में एकता और अखंडता के सूत्र ढूंढेगा उसे सारा भारत बहुरंगी गुलदस्ता दिखेगा। भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी अनुवाद और मौलिक अनुप्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ रही है और साहित्य, हिंदी फिल्म, ओ.टी.टी. में तो दुनिया के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बना ली है।

बैठक के प्रारंभ में पश्चिम रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री विनीत गुप्ता ने समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक सहित सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर में विभागीय वेबसाइटों के नियमित अद्यतन तथा उन पर सामग्री के द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में अधिकारियों के लिए एक राजभाषा प्रश्न-मंच का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। पश्चिम रेलवे में जनवरी से मार्च-2026 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति संबंधी आंकड़े समिति की सदस्य सचिव श्रीमती सुनीता अहिरे द्वारा प्रस्तुत किए गए।

पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस बैठक में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री नरेंद्र पाटील, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सड़क संरक्षा परियोजनाएं) श्री विनोद कुमार, प्रमुख वित्त सलाहकार श्रीमती ऋचा खरे, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री विद्याधर अविनाश मालेगांवकर, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री सहर्ष वाजपेयी, श्री अमित गुप्ता, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, श्री रजनीश कुमार, प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक, उप महाप्रबंधक (सामान्य) श्री उज्ज्वल देव, सचिव/पश्चिम रेलवे श्री सचिन अशोक शर्मा सहित सभी मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंधक आदि अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

मही नदी पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से साकार होगा 'बदलपुर कारेली बैराज कम ब्रिज' : तीन जिलों के विकास को मिलेगी नई दिशा

- धुवारण के पास मही नदी पर बनेगा भव्य बैराज, खारेपन में आएगी कमी तथा 75 किलोमीटर की दूरी घटेगी
- चरोत्तर से भरूच तक का क्षेत्र बनेगा समृद्धि का नया पता
- बदलपुर बैराज परियोजना को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा राज्य के समुद्र तटीय तथा नदी तटीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक और ऐतिहासिक एवं जनहितकारी निर्णय लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी के प्रयासों के परिणामस्वरूप आणंद जिले में मही नदी पर धुवारण के पास 'बदलपुर–कारेली बैराज कम ब्रिज' के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में लगभग 1700 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना केवल दो भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला सेतु ही नहीं, बल्कि मध्य एवं दक्षिण गुजरात में कृषि, पेयजल तथा परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली सिद्ध होगी। सरकार ने इस योजना के लिए सर्वेक्षण कार्य को अत्यंत तेजी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा लिया गया यह दूरदर्शी निर्णय मध्य गुजरात तथा दक्षिण गुजरात के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। जल, परिवहन और प्रगति का यह त्रिवेणी संगम चरोत्तर से भरूच तक के क्षेत्र को समृद्धि का नया पता बनाएगा।

यह आधुनिक बैराज कम ब्रिज स्थापत्य कला और आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। आणंद सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री रजत चौधरी के अनुसार; इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 4.5 किलोमीटर चौड़े मही नदी के बीच लगभग 2 किलोमीटर भाग में पुल का निर्माण किया जाएगा। नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने तथा वर्षा ऋतु में बह जाने वाले मीठे पानी का अधिकतम संग्रह करने के उद्देश्य से लगभग 70 दरवाजे लगाए जाएंगे। शेष भाग में प्रोटेक्शन बंध का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण टेक्नोलॉजी तथा मजबूत क्रॉस-वे प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिससे भारी वर्षा अथवा बाढ़ की स्थिति में भी यातायात तथा जल भंडारण सुरक्षित रह सके।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल जल भंडारण क्षमता है। बैराज बनने के बाद लगभग 183 मिलियन घन मीटर मीठे पानी का संग्रह किया जा सकेगा। हर वर्ष मही नदी का लाखों लीटर मीठा पानी प्रतिवर्ष समुद्र में बह जाता है, जिसे इस बैराज के माध्यम से रोका जा सकेगा।

वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों की पेयजल आवश्यकता का मुख्य आधार कडाणा बांध है। बैराज के निर्माण के बाद कडाणा बांध पर निर्भरता कम होगी तथा संग्रहित जल आसपास के क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध होगा। भविष्य में यह जल उद्योगों, कृषि तथा स्थानीय आबादी के लिए जल संकट को स्थायी रूप से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वर्तमान में इस क्षेत्र में समुद्र का पानी सिंधरोट वीयर तक यानी लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर जाता है। लंबे समय से समुद्री ज्वार के कारण इस क्षेत्र की भूमि में खारापन एक गंभीर समस्या रही है। बदलपुर बैराज के निर्माण से बड़े पैमाने पर मीठे पानी का संग्रह होने के कारण भूमि की लवणता की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इससे लगभग 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मीठे पानी के प्रभाव से भूजल की गुणवत्ता में भी चरणबद्ध रूप से उल्लेखनीय सुधार होगा। खारापन कम होने से किसान वर्ष में अनेक फसलें ले सकेंगे, जिससे स्थानीय कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आएगी तथा भूमि की उर्वरता पुनः जीवित होगी।

जल वितरण व्यवस्था की दृष्टि से भी यह बैराज कम ब्रिज योजना सामाजिक स्तर पर बड़ा परिवर्तन लाएगी। इसके पूर्ण होने पर आणंद जिले के 42 गांव, वडोदरा जिले के 30 गांव तथा भरूच जिले के 8 गांव सहित लगभग 80 गांवों के 15 लाख से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

यह परियोजना केवल जल संग्रहण तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी ब्रिज के रूप में भी कार्य करेगी। खंभात एवं तारापुर से जंबूसर तथा दहेज औद्योगिक क्षेत्र के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे प्रतिदिन हजारों लीटर पेट्रोल एवं डीजल की बचत होगी तथा बहुमूल्य समय भी बचेगा। दहेज पीसीपीआईआर तथा खंभात–तारापुर क्षेत्र के बीच माल परिवहन तेज होने से व्यापार एवं उद्योग को नई गति मिलेगी।

यह योजना केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल देगी। आणंद के 152, वडोदरा के 164 तथा भरूच के 81, कुल मिलाकर 409 गांवों एवं 32 तालाबों को इस योजना का परोक्ष लाभ भी मिलेगा। कृषि एवं उद्योगों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। इसके अतिरिक्त; नदी किनारे विशाल जलराशि के एकत्र होने से भविष्य में यह क्षेत्र एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है, जो स्थानीय लोगों के लिए आय का नया स्रोत बनेगा।

मही नदी पर शुरु होने वाली बदलपुर–कारेली बैराज कम ब्रिज परियोजना गुजरात की विकास यात्रा में एक नया मील का पत्थर सिद्ध होगी।

26 जून : अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस

गुजरात पुलिस ने पिछले पाँच वर्षों में 13,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स को न केवल गुजरात, बल्कि अन्य राज्यों के युवाओं तक पहुँचने से भी रोका

- ड्रग माफियाओं के विरुद्ध गुजरात पुलिस का प्रहार : 5 वर्षों में 3,700 से अधिक मामले दर्ज कर नशे के काले कारोबार से जुड़े कुल 5,346 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला
- आज ड्रग्स का कारोबार करने वाले माफिया गुजरात के रास्ते अन्य राज्यों में अपना माल ले जाने से भी काँप रहे हैं : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
- गुजरात पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क की कमर तोड़ी : राज्य पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक
- ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मुखबिरों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए 'ड्रग रिवॉर्ड पॉलिसी' लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य
- अपनी जान के जोखिम पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' देने की ऐतिहासिक नीति लागू
- स्थानीय पुलिस थानों की टीमें भी अब नारकोटिक्स के मामले दर्ज कर रही हैं

गांधीनगर : 26 जून यानी 'अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस'। गुजरात पुलिस मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी के सबल एवं आक्रामक नेतृत्व में देश की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाले राज्य गुजरात को ड्रग-फ्री स्टेट बनाने तथा मादक पदार्थों की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी गुजरात पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियाँ माफियाओं के ड्रग्स की हेराफेरी करने के लिए रचे जाने वाले नए-नए षड्यंत्रों को विफल कर रही हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस की आक्रामक कार्रवाई के परिणामस्वरूप आज ड्रग्स का कारोबार करने वाले माफिया गुजरात के रास्ते अन्य राज्यों तक अपना माल पहुँचाने से भी काँप रहे हैं।

राज्य में नशे के कारोबार के दमन के लिए पिछले पाँच वर्षों में की गई कार्रवाइयों का विवरण देते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक ने कहा कि गुजरात सरकार ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर कड़ाई से लागू भी किया है। राज्य में ड्रग्स की हेराफेरी एवं व्यापार के विरुद्ध 3,700 से अधिक मामले दर्ज कर नशे के काले कारोबार से जुड़े 5,346 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। इन रणनीतिक अभियानों के अंतर्गत पुलिस ने लगभग 13,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 1.36 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त कर अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क की कमर तोड़ी है।

गुजरात की क्रांतिकारी 'ड्रग रिवॉर्ड पॉलिसी' और पुलिस को 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' नीति से विशेष प्रोत्साहन

कोई युद्ध तभी जीता जा सकता है, जब उसे लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल आसमान पर हो। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बना है, जिसने आधिकारिक रूप से 'ड्रग रिवॉर्ड पॉलिसी' लागू की है। इस नीति के तहत ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाले तथा करोड़ों रुपए मूल्य का नशीला पदार्थ पकड़ने वाले साहसी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सटीक सूचना देने वाले आम नागरिकों तथा मुखबिरों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

इतना ही नहीं; सरकार ने परंपरागत सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी जान के जोखिम पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को 'आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन' देने की ऐतिहासिक नीति अपनाई है। इस क्रांतिकारी कदम से पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ा है और अब हर स्तर का पुलिस कर्मचारी इस लड़ाई में सक्रिय रूप से जुड़ गया है।

एआई आधारित 'एनएआरआईटी' सॉफ्टवेयर तथा कन्विक्शन रेट बढ़ाने का लक्ष्य

आधुनिक युग के ड्रग माफिया डिजिटल और अत्याधुनिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ऐसे में उनसे मुकाबला करने के लिए गुजरात पुलिस ने भी हाई-टेक तकनीक को अपनाया है। ड्रग अपराधियों की प्रोफाइलिंग एवं कनेक्शन ट्रैकिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी-बेस्ड इन्वेस्टिगेशन यानी 'एनएआरआईटी-नैरिट' सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य बना है।

इस सॉफ्टवेयर की सहायता से पकड़े गए अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड, उनके अंतरराष्ट्रीय संपर्क, वित्तीय लेन-देन तथा डार्क वेब से जुड़े तारों को कुछ ही सेकंड में स्कैन कर इंटेलिजेंस डाटाबेस तैयार किया जाता है। जाँच में केवल स्थानीय पेडलरों तक सीमित न रहते हुए अपराध की जड तक पहुँचने के लिए 'टॉप टू बॉटम एप्रोच' को अपनाया गया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत दर्ज मामलों को अदालत में अधिक मजबूत बनाने, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और राज्य की कन्विक्शन दर बढ़ाने के लिए चार्जशीट तथा साइंटिफिक साक्ष्यों का विश्लेषण भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

ड्रग्स के विरुद्ध रणनीतिक एक्शन प्लान

एएनटीएफ की स्थापना : ड्रग्स के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए विशेष 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स' (एएनटीएफ) का गठन किया गया है।

स्थानीय पुलिस को अधिकार : राज्य पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक के निर्देश पर अब केवल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) या आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ही नहीं, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशन भी नारकोटिक्स के मामले दर्ज कर उनकी सीधी जाँच कर सकेंगे।

माइक्रो-लेवल एंटी-नारकोटिक्स सेल : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गाँवों तक तक नशे का प्रसार रोकने के लिए प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड सेल का गठन करने की कवायद शुरू की गई है।

गुजरात पुलिस की सक्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020 में जहाँ राज्य में नारकोटिक्स के केवल 315 मामले दर्ज हुए थे, वहीं चालू वर्ष में शुरुआती पाँच महीनों में ही 584 मामले दर्ज हुए हैं। मामलों की संख्या में यह वृद्धि ड्रग्स के बढ़ते प्रसार का संकेत नहीं है, बल्कि पुलिस के सर्वेलांस, रेड करने की क्षमता तथा 'जीरो टॉलरेंस' नीति अंतर्गत अधिक से अधिक अपराधों का पता लगाने की आक्रामकता को दर्शाती है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी का मानवीय दृष्टिकोण

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी के अनुसार, "यह लड़ाई केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे की दलदल में फँसे राज्य के युवाओं को सुरक्षित बाहर निकालने की भी है।" इस विचारधारा के साथ राज्य सरकार अपराधियों के प्रति वज्र जैसी कठोर होने के साथ-साथ नशे के शिकार बने युवाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील भी है, जिसके अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्रों को अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया गया है। युवा फिर से सम्मानपूर्वक समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें; इसके लिए उन्हें उचित काउंसिलिंग और चिकित्सीय उपचार प्रदान किए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर गुजरात पुलिस की यह आक्रामक नीतियाँ, टेक्नोलॉजी का विवेकपूर्ण उपयोग तथा सरकार का दृढ़ संकल्प देशभर के राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बना है। गुजरात 'ड्रग-फ्री स्टेट' बनने की दिशा में निरंतर और दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है।

कन्या केळवणी महोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव 2026 : तीसरा दिन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साणंद तहसील के पींपण गांव और साणंद मॉडल स्कूल में बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराया

▸▸ कन्या केळवणी और शाला प्रवेशोत्सव सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन-जन का उत्सव बन गया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर का दौरा कर स्मार्ट सुविधाओं का निरीक्षण किया और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के साथ बैठक की

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ 2003 में श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बोया गया प्रवेशोत्सव का बीज आज वटवृक्ष बन गया है : स्कूलों में 100 फीसदी नामांकन और जीरो ड्रॉपआउट दर का लक्ष्य

▸▸ जब साणंद सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, ऐसे में जरूरी है कि हमारे बेटे-बेटियां भी ग्लोबल स्तर की शिक्षा प्राप्त करें

▸▸ औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से पर्यावरण संरक्षण और 'कैच द रेन' के जरिए जल संचय से जल सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ कहा कि 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया कन्या केळवणी (शिक्षा) और शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आज केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि अभिभावकों, शिक्षकों और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से जन-जन का लोकात्सव बन गया है।

राज्य में शिक्षा के स्तर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और 100 फीसदी नामांकन के लक्ष्य के साथ मनाए जा रहे 24वें 'शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी महोत्सव 2026' के तीसरे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद जिले की साणंद तहसील के पींपण गांव और मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को उत्साह के साथ शाला प्रवेश कराया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा का महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के चलते आज स्कूलों में 100 फीसदी नामांकन हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले (ड्रॉपआउट) विद्यार्थियों की सूची तैयार करके और अभिभावकों की काउंसलिंग करके उन्हें पुनः स्कूल में लाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रहपूर्वक कहा कि आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मॉडल स्कूल साणंद में कक्षा 9 में 142 विद्यार्थियों, कक्षा 11 सामान्य संकाय में 50 विद्यार्थियों और कक्षा 11 विज्ञान संकाय में 17 विद्यार्थियों सहित कुल 209 विद्यार्थियों का शाला प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को शैक्षणिक किट प्रदान कर प्रवेश दिलाया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शाला प्रवेशोत्सव की सफलता को लेकर कहा कि दो दशक पहले श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया शाला प्रवेशोत्सव आज एक वटवृक्ष बन चुका है। पहले स्कूल जाते समय रोने वाले बच्चों के स्थान पर, आज विद्यार्थियों के चेहरे पर अद्भुत आनंद और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, जो दिखाता है कि यह सरकारी कार्यक्रम न रहकर सही मायनों में जन-जन का उत्सव बन गया है।

साणंद के औद्योगिक विकास की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और साणंद देश का बड़ा 'सेमीकंडक्टर हब' बनकर उभर रहा है, तब यह जरूरी है कि इस क्षेत्र के बेटे-बेटियां भी ग्लोबल स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि आज राज्य के सरकारी स्कूलों की छवि इतनी बदल चुकी है कि उनमें एडमिशन के लिए सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, जो शिक्षा नीति की बड़ी उपलब्धि है।

ग्लोबल वॉर्मिंग के चुनौतीपूर्ण समय में पर्यावरण और जल संचय की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू की गई 'कैच द रेन' मुहिम के अंतर्गत बरसाती पानी की बूंद-बूंद का संग्रह करना और उसे जमीन में उतारना हमारी भावी पीढ़ियों की जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। विधायकों को रिचार्जिंग बोर बनाने के लिए 50 लाख रुपए का विशेष अनुदान आवंटित किया गया है। पर्यावरण संतुलन के लिए प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की भावपूर्ण अपील की।

सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला और आवास योजना जैसे सभी लाभों के मिलने से पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गया है।

प्रगति का प्रवेशोत्सव थीम के साथ आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और महानुभावों ने स्कूल के प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करे वाले विद्यार्थियों का विशेष सम्मान किया। स्कूल का सौ फीसदी परिणाम लाने के लिए प्राचार्य श्री विनोदभाई मगवाड़िया तथा स्कूल को उदार हाथों से दान देने वाले दाताओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रेरणादायी वक्तव्य दिए।

मुख्यमंत्री ने साणंद मॉडल स्कूल परिसर का दौरा किया। उन्होंने अत्याधुनिक गतिविधि-आधारित साइंस लैब का जायजा लिया और शैक्षणिक सुविधाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गर्ल्स हॉस्टल का दौरा करके वहां कि व्यवस्थाओं को देखा। मुख्यमंत्री ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और स्कूल प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) के सदस्यों और अभिभावकों के साथ बैठक कर संवाद किया, जिसमें स्कूल के सर्वांगीण विकास, ड्रॉपआउट की दर कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के बारेर में अहम चर्चा-विचार किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के संदेश के साथ स्कूल प्रांगण में सामूहिक वृक्षारोपण किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुरजीतसिंह गोहिल, साणंद के विधायक श्री कनुभाई पटेल, अहमदाबाद जिला कलेक्टर श्री भव्य वर्मा, जिला विकास अधिकारी श्री विदेह खरे, पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश जाट, अग्रणी श्री शैलेषभाई दावड़ा, नपा अध्यक्ष श्री ध्रुमिनभाई जोशी, जिला पंचायत और तहसील पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यगण, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों और अभिभावकों सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने विद्यार्थियों को केवल होशियार नहीं, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनाने की अपील की

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में खोड़ियार नगर स्थित महारानी शांतादेवी प्राथमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव आयोजित

▸▸ उप मुख्यमंत्री ने 1354 बच्चों द्वारा निजी स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल में दाखिला लेने को शिक्षा समिति और वडोदरा जिला प्रशासन की सफलता बताया

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता और महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. मनीषा वकील की प्रेरक उपस्थिति में गुरुवार को वडोदरा जिले के खोड़ियार नगर स्थित महारानी शांतादेवी प्राथमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव एवं कन्या केळवणी (शिक्षा) महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने सभी शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि अभिभावक और परिवार बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षकों को सौंपते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे उनके विश्वास को कायम रखते हुए बच्चों के जीवन का निर्माण करें। बतौर शिक्षक यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिसे निष्ठापूर्वक निभाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे बच्चों से अपील की कि वे रट्टा मारकर पढ़ने के बजाय हंसते-खेलते बिना बोझ के शिक्षा प्राप्त करें।

श्री संघवी ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पढ़ाई में व्यस्त रखने बजाय उनमें खेल, विज्ञान, संगीत और कला के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए, जिससे वे जीवन में आने वाली हार-जीत का सामना करते हुए एक सक्षम नागरिक बन सकें। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन की आदत के रूप में विकसित करने की सीख दें।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वडोदरा नगर शिक्षण समिति के हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती मीडियम के स्कूलों में 49,924 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस वर्ष 7544 बच्चों ने प्रवेश लिया है, जबकि 1354 बच्चों ने निजी स्कूल छोड़कर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया है। उन्होंने इसे शिक्षा समिति और वडोदरा जिला प्रशासन की सफलता बताया। साथ ही, उन्होंने ड्रॉपआउट हुए यानी स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को घर-घर जाकर फिर से प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा समिति और वडोदरा जिला प्रशासन को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने आंगनवाड़ी, बालवाटिका और कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया और उनके शैक्षणिक जीवन की नई शुरुआत पर उन्होंने प्रोत्साहित किया।

नगर प्राथमिक शिक्षा समिति वडोदरा में शाला प्रवेशोत्सव के दौरान बालवाटिका में 4167 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। वहीं, कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूलों से आए विद्यार्थियों सहित कुल 7544 विद्यार्थियों ने नया प्रवेश लिया। शाला प्रवेशोत्सव के तहत दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी विद्यार्थियों, दिव्यांग खिलाड़ियों और पुनः प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री सहित उपस्थित महानुभावों ने स्कूल परिसर का दौरा किया।

नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शासनाधिकारी डॉ. विपुल भरतिया ने स्वागत भाषण में कहा कि वडोदरा शिक्षा समिति के 'विजन 2030' के साथ वडोदरा शहर की सभी इंडस्ट्री और सीएसआर संस्थानों को जोड़ा जाएगा। स्कूल के अंदर हाईटेक सुविधाओं के साथ-साथ विद्यार्थियों को अनुभवजन्य शिक्षा मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आसानी होगी।

कार्यक्रम में विधायक श्री चैतन्य देसाई, वडोदरा की महापौर श्रीमती गीताबेन मकवाणा, उप महापौर श्री आदित्यभाई पटेल, शिक्षा समिति की अध्यक्ष अंजनाबेन ठक्कर, आयुक्त श्री अरुण महेश बाबू, संगठन प्रमुख जयप्रकाश सोनी, स्थानीय समिति की अध्यक्ष वर्षाबेन व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी श्री महेश पांडे और बीआरसी श्री मुकेश शर्मा सहित स्थानीय पदाधिकारी, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मंडल के डीआरएम ने साबरमती में आरओएच डिपो और स्टेशन पुनर्विकास कार्यों का किया गहन निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने साबरमती स्थित रूटीन ओवरहॉलिंग (ROH) वैगन डिपो तथा साबरमती रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालगाड़ी वैगनों के अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा, उपलब्ध सुविधाओं का आकलन तथा स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया।

आरओएच डिपो में अनुरक्षण व्यवस्था का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने शेड में उपलब्ध अनुरक्षण संसाधनों एवं मशीनों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में अनुरक्षण कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन पर्याप्त उपलब्ध हैं। भविष्य में नए एंड ऑफ ट्रेन (EOT) क्रेन स्थापित किए जाने के मद्देनजर शेड को और सुदृढ़ बनाने की योजना पर भी चर्चा की गई। डीआरएम ने साबरमती आरओएच डिपो में अनुरक्षण संसाधनों और मशीनों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से वर्तमान में उपलब्ध 68 आरओएच और 67 सिक लाइन वैगनों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एक बीएफकेएचएन वैगन के सेंटर बफर कपलर (CBC) के अनुरक्षण कार्य का निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों से अनुरक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता संतोषजनक पाई गई।

सुरक्षा एवं अनुरक्षण सुविधाओं की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान ईओटी क्रेन की चेन परीक्षण व्यवस्था, इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर, एयर रिजर्वायर टैंक, स्टोर रूम, यार्ड इंचार्ज कार्यालय, टीएक्सआर कार्यालय, लॉकर रूम, यार्ड स्टोर तथा अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। स्टोर की सुव्यवस्थित व्यवस्था एवं सामग्री के रखरखाव की सराहना की गई।

संचालन में सुधार हेतु दिए आवश्यक निर्देश

डीआरएम ने वैगनों के समय पर अनुरक्षण, सामग्री की उपलब्धता, शेड में वैगनों की समयबद्ध प्लेसमेंट, अनुरक्षण कार्यों में समन्वय तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सामग्री की कमी, वैगनों के अनावश्यक ठहराव तथा यार्ड संचालन से संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान यार्ड की प्रकाश व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अपर्याप्त रोशनी को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक मानकों के अनुरूप प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही लाइन संख्या 5 एवं 6 के मध्य पक्के मार्ग के निर्माण, जल निकासी व्यवस्था में सुधार तथा वैगन परीक्षण दलों के निष्क्रिय समय को कम करने के लिए बेहतर परिचालन योजना बनाने पर बल दिया गया।

साबरमती स्टेशन पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने साबरमती रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने हाई रूफ ट्रस की लॉन्चिंग, प्लेटफॉर्मों पर चल रहे निर्माण कार्य, यात्री सुविधाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

डीआरएम ने निर्माण एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष हाई रूफ ट्रस निर्धारित समयसीमा में स्थापित किए जाएं तथा ट्रस लॉन्चिंग के साथ-साथ फिनिशिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य भी समानांतर रूप से किए जाएं ताकि परियोजना समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सके।

यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर वैकल्पिक यात्री शेड उपलब्ध कराने, अस्थायी शेड को मानसून के अनुरूप मजबूत बनाने तथा यात्री सुविधाओं को निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या-2 एवं 3 के सभी पुनर्विकास कार्य 15 अगस्त 2026 तक तथा प्लेटफॉर्म संख्या-1 सहित परिसंचरण क्षेत्र, कॉनकोर्स एवं अन्य यात्री सुविधाओं के कार्य सितंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

स्टेशन भवन के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण पर जोर

डीआरएम ने नए स्टेशन मास्टर कक्ष, वीआईपी कक्ष और प्रवेश द्वार (कैनोपी) के डिजाइन में आवश्यक संशोधनों के साथ-साथ स्टेशन के आधुनिक और आकर्षक स्वरूप पर जोर दिया। उन्होंने बुलेट ट्रेन भवन की ओर जाने वाले प्रवेश मार्ग के बेहतर विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा। श्री वेद प्रकाश ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें।

समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर दिया विशेष बल

निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को सभी विकास एवं अनुरक्षण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-केंद्रित रेल सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद मंडल माल परिवहन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक एवं विश्वस्तरीय रेलवे अवसंरचना विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

जेसी बैंक अहमदाबाद शाखा द्वारा दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम आयोजित

अहमदाबाद, 25 जून 2026: जे.सी.सी.एस. बैंक (The Jackson Co-operative Credit Society Ltd.) की अहमदाबाद शाखा द्वारा 25 जून 2026 को दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के सम्मान एवं आर्थिक सहयोग हेतु एक भावनात्मक "सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन दिवंगत अंशधारकों के परिवारों के प्रति बैंक की संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पारिवारिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करना था, जिन्होंने अपने सेवाकाल में भारतीय रेल एवं बैंक के प्रति समर्पण एवं निष्ठा के साथ सेवाएं प्रदान की थीं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश रहे। उन्होंने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को सम्मान निधि, आर्थिक सहायता तथा विभिन्न लाभों के चेक वितरित किए।

अपने संबोधन में श्री वेद प्रकाश ने दिवंगत रेलकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय रेल अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के साथ सदैव खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ रेलवे की सेवा की है, उनके परिवारों के प्रति रेल प्रशासन की भी समान जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पास, पेंशन अथवा रेल प्रशासन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए रेल प्रशासन इन परिवारों को अपने परिवार का सदस्य मानकर हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि पूर्व में अनेक रेल कर्मचारी बेटी के विवाह, मकान निर्माण अथवा अन्य आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों से अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हो जाते थे, जिससे वे आर्थिक शोषण का शिकार बनते थे। उन्होंने कहा कि जेसी बैंक ने रेल कर्मचारियों को सरल प्रक्रिया एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है।

09 दिवंगत अंशधारकों का 44.31 लाख का ऋण पूर्णतः माफ

कार्यक्रम के दौरान बैंक प्रबंधन ने मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अहमदाबाद शाखा के 09 दिवंगत अंशधारकों की कुल बकाया ऋण राशि 44,31,782/- (चौवालीस लाख इकतीस हजार सात सौ बयासी रुपये) को पूर्णतः माफ करने की घोषणा की। यह निर्णय दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में बैंक की एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पहल है।

28.86 लाख की जमा पूंजी एवं 50,000 की अनुग्रह राशि प्रदान

बैंक द्वारा दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को उनकी Compulsory Thrift Deposit (CTD) में जमा 28,86,275/- की पूंजी का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पात्र परिवार को बैंक की ओर से 50,000/- की अनुग्रह राशि के चेक भी प्रदान किए गए, जिससे उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त हो सके।

तुलसी का पौधा भेंट कर किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान सभी आश्रित परिवारों को बैंक की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। यह पौधा सकारात्मकता, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं का प्रतीक रहा।

बैंक भवन के आधुनिकीकरण का दिया आश्वासन

कार्यक्रम के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने जेसीसीएस बैंक के वर्तमान भवन का निरीक्षण किया। भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बैंक के लिए आधुनिक एवं बेहतर भवन के निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के अंत में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जेसी बैंक अपने सदस्यों एवं उनके परिवारों के साथ सदैव एक परिवार की तरह खड़ा रहा है और भविष्य में भी सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय सेवा तथा सदस्य हितों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की पूर्व तैयारियां तेज, 30 जून को सिग्नलिंग सिस्टम को किया जायेगा अपग्रेड : DRM राजू भडके

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा परिचालन क्षमता बढ़ाने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य प्रगति पर है। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा स्टेशन यार्ड का अधिकारिओं एवं रेलवे इंजीनियरों के साथ दौरा किया गया और कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारिओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कार्य के दौरान रेल परिचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और यात्रिओं को मिनिमम असुविधा हो। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्रीमती रिनी , वरिष्ठ मंडल इंजीनियर श्री सुमित ठाकुर , वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (ट्रैक्शन) श्री नलिन लोचन गुप्ता , वरिष्ठ मंडल सिग्नलिंग & टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर श्री विपुल गुप्ता , उप मुख्य सिग्नलिंग & टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर श्री अपूर्व तिवारी, मंडल परिचालन प्रबंधक (सामान्य) परवेज खान, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर श्री आभास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने बताया कि यार्ड रिमॉडलिंग के इस महत्वपूर्ण कार्य में गुणवत्ता और संरक्षा मानकों के साथ साथ साथ यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि समय पर नॉन इंटरलॉकिंग के पूर्व के सभी कार्य पूरे किये जाए। 30 जून को नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जायेगा और वडोदरा स्टेशन का सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड हो जायेगा। अभी यात्रिओं की सुविधा के लिए प्लेटफार्म नंबर 4 एवं 5 की लम्बाई बढ़ाने का कार्य चल रहा है। इससे इन प्लेटफॉर्मों पर 22 कोच वाली ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। वर्तमान में प्लेटफॉर्म संख्या 4 की लंबाई 498 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 592 मीटर किया जाएगा। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म संख्या 5 की वर्तमान लंबाई 498 मीटर से बढ़ाकर 568 मीटर की जाएगी। जिसके लिए टर्न आउट , सिग्नल और ओवर हेड वायर की शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए प्लेटफार्म नंबर 5 & 6 पर ट्रेन परिचालन स्थगित किया गया है। यह यार्ड रीमॉडलिंग एवं प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य वडोदरा स्टेशन की परिचालन क्षमता को और सुदृढ़ करेगा तथा भविष्य की यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर एवं अधिक कुशल रेल सेवाएँ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

किसानों के खेतों में 1,50,000 खंभे लगाए जाने हैं: इसुदान गढ़वी

अहमदाबाद/मोरबी/गुजरातः मोरबी के जेतपर में किसान उपवास पर बैठे हैं, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित करते हुए 'आप' नेता इसुदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात के किसानों पर इस समय भाजपा सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। भाजपा सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है मानो वह कंपनियों की मालिक बन गई हो! कंपनियां निजी रूप से कमाई करने आई हैं और उन्हें करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाना है, लेकिन अब कंपनियां किसानों की कीमत पर मुनाफा कमाने के लिए तैयार हो गई हैं। भाजपा सरकार इन कंपनियों के साथ मिलकर, उनके पक्ष में खड़ी होकर पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराकर किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज मोरबी के जेतपर में जो किसान अपनी बहुमूल्य जमीन बचाने के लिए पिछले आठ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। उनकी तबीयत अब नाजुक होने लगी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के एक सिपाही के रूप में मुझे और आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत चिंता हो रही है कि यह बहरी-गूंगी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एसी चेंबर में आराम कर रहे हैं, जबकि पूरे देश को अनाज खिलाने वाला मेरा किसान आज भूखा बैठा है। इस समय किसानों की हालत बहुत नाजुक हो गई है, इसलिए सरकार से हमारी पहली मांग है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जेतपर गांव के लोगों से मिलें, उनकी मांगों को यथासंभव स्वीकार करें और जल्द से जल्द उनका अनशन तुड़वा कर समाप्त करवाएं। मुझे जहां तक जानकारी है, यह भाजपा के ही एक मंत्री का गांव है। उसी मंत्री के गांव में पहले किसानों पर लाठियां बरसाई गईं और अब किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। इसलिए सरकार एक घंटे का भी समय बर्बाद किए बिना मुख्यमंत्री स्तर पर इन किसानों के साथ तुरंत बैठक करे और इस समस्या का उचित समाधान निकाले।

इसुदान गढ़वी ने आगे कहा कि दूसरी मेरी बात यह है कि यह केवल जेतपर का ही मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार जानकारी मिली है और समाचार पत्रों में भी छपा है, उसके अनुसार गुजरात में निजी कंपनियों और भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के बीच गुप्त बैठकें हुई हैं। पूरे गुजरात में मकड़ी के जाले की तरह खंभे लगाकर हाईटेंशन बिजली लाइनें बिछाने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। सरकार को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी लाइनें डाली जानी हैं, कब डाली जानी हैं और किस प्रकार डाली जानी हैं? हमें मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह योजना केवल जेतपर, मोरबी, कच्छ, द्वारका, राजकोट या जामनगर तक सीमित नहीं है। सरकार ने गुजरात के 26 जिलों से ऐसी 100 भारी हाईटेंशन लाइनें निकालने का निर्णय किया है। वह भी किसानों की कीमत पर और उनकी उपजाऊ जमीन से, किसी बंजर जमीन से नहीं! अनुमानतः एक लाइन की लंबाई 500 किलोमीटर है और ऐसी 100 लाइनें डालने का निर्णय लिया गया है। यदि एक लाइन में लगभग 1500 खंभे आते हैं, तो सोचिए कि 100 लाइनों में कितने खंभे आएंगे? यानी लगभग डेढ़ लाख खंभे किसानों के खेतों में, उनकी कलेजे के टुकड़े समान जमीन की छाती चीरकर लगाए जाएंगे और इसके लिए पुलिस संरक्षण भी तैयार रखा गया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों पर अत्याचार करना बंद करें। आप किसानों पर अत्याचार करेंगे, पुलिस भेजेंगे, झूठे मुकदमे करेंगे, डराएंगे या धमकाएंगे, तो शायद किसान कुछ समय के लिए पीछे हट जाएंगे, लेकिन कम से कम ईश्वर और अपने भगवान का तो डर रखिए! यदि आपकी यह योजना किसानों के हित में है, तो स्थानीय स्वराज्य चुनावों से पहले आपने यह काम क्यों शुरू नहीं किया? यदि आपकी नीयत साफ होती तो सरकार किसानों के साथ समझौता करती। यदि मुआवजा पूरा नहीं देना है और अन्याय ही करना है, तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि चुनाव से तीन महीने पहले, अक्टूबर 2027 में इन खंभों को लगाने का काम शुरू करके दिखाइए, तब पता चलेगा कि आपमें कितनी हिम्मत है! स्थानीय स्वराज्य चुनाव खत्म हो गए और विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़-दो साल का समय बाकी है, तब आपने यह काम शुरू किया है। इसलिए सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इसमें मेरे लाखों किसान पीड़ित हो रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, प्रति किलोमीटर 77 बीघा जमीन इससे प्रभावित होती है। मैं सभी किसानों से भी कहना चाहता हूं कि अब सभी एक हो जाइए। आज यह आपदा किसी एक के खेत में है, कल आपके भाई के या आपके खेत में आएगी, क्योंकि यह करोड़ों रुपये की बड़ी योजना है। इस योजना से लगभग 38 लाख बीघा जमीन पर खंभे लगने की संभावना है, जिसमें साढ़े पांच लाख से अधिक किसान और उनके परिवार तथा मजदूर मिलाकर लगभग 30 से 40 लाख लोग प्रभावित होने वाले हैं, फिर भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

इसुदान गढ़वी ने आगे कहा कि सरकार से मेरी सीधी मांग है कि इस मुद्दे पर कलेक्टर स्तर की नहीं बल्कि राज्य स्तर (State Level) की 'मुआवजा समिति' का गठन किया जाए। इस समिति में उच्च अधिकारी, केंद्र के प्रतिनिधि और साथ ही प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। मुआवजा इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि अगले 25 वर्षों बाद जमीन की जो अनुमानित कीमत होगी, उसे ध्यान में रखा जाए। सरकार किसानों को इस योजना में भागीदार बनाए या फिर ऐसा मुआवजा दे कि प्रति खंभा प्रति माह एक लाख रुपये जैसा किराया मिले। जो भी मुआवजा तय हो, उसमें किसानों की सहमति अनिवार्य हो। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है और इस मामले में हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। आगामी 27 तारीख को सुरेंद्रनगर में शाम 4 बजे आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य स्तरीय 'किसान महापंचायत' का आयोजन किया गया है। जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम दिए जाएंगे। यदि सरकार हमारी इन न्यायसंगत मांगों को स्वीकार नहीं करती, तो आगामी समय में सभी जिलों में आम आदमी पार्टी इस हाईटेंशन लाइन के विरोध में उग्र कार्यक्रम करेगी। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने आदिवासी समाज की आवाज बनने का 'गुनाह' किया है, आदिवासियों को जागरूक करने का काम किया है, उनके खिलाफ सरकार दुर्भावना रख रही है। भाजपा ने साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाकर, डराकर-धमकाकर उन्हें भाजपा में लाने के सभी प्रयास किए, लेकिन जब वे प्रयास असफल हो गए तो चैतरभाई वसावा पर डे-टू-डे (रोजमर्रा) मुकदमा चलाकर सात साल की सजा करवा दी गई।